बैंकों की लेखा-परीक्षा

3382 **श्री आस मोहम्मद :**

चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनसूचित वाणिज्यिक बैंकों में समवर्ती लेखा-परीक्षा चार वर्ष में एक बार होने के कारण बैंकों में भ्रष्टाचार हो रहा है ;

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा लेखा-परीक्षा चार वर्ष की बजाय दो वर्ष में करवाए जाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने बताया है कि बैंकों में भ्रष्टाचार के लिए समवर्ती लेखा-परीक्षा की आवश्किता की उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि समवर्ती लेखा-परीक्षा एक सतत प्रक्रिया है ।

(ग) 1 करोड़ रुपए की आग्रेम रशि वाली शाखाओं की लेखा-परीक्षा अनिवार्य रूप से प्रत्येक वर्ष कराई जाती है । शेष शाखाओं में से चौथाई शाखाओं की लेखा-परीक्षा भी प्रतिवर्ष की जाती है । फलस्वरूप कुल शाखाओं के 63 प्रतिशत शाखाओं की लेखा-परीक्षा प्रतिवर्ष की जाती है । परन्तु यदि सभी शाखाओं की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से दो वर्षों में एक बार की जाती है तो इससेन केवल लागत में वृद्धि होगी बल्कि बैंकों के अन्तिम लेखाओं को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में भी विलम्ब होगा ।

भारतीय रिजर्व बैंक की नई ऋण नीति

3383. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक की नई ऋण-नीति के क्या उद्देश्य हैं ;

(ख) क्या विभिन्न बैंकों तथा ऋण लेने वाले व्यक्तियों के बीच अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है ;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार नई ऋण-नीति को कारगर ढंग से लागू करने के लिए प्रभावशाली बाजार निगरानी प्रक्रिया आरम्भ करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (एम० वी० **चन्द्रशेखर मूर्ति**) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने बताया है कि वर्ष 1995–96 के उत्तरार्ध के लिए दिनांक 17 अप्रैल 1995 को घोषित मौद्रिक एवं ऋण नीति का उद्देश्य समग्र चलनिधि में मुद्रा स्फीति दर एवं प्रसार को सीमित करना है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि मौद्रिक एवं ऋण नीति की लगातार पुनरीक्षा की जाती है और बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसमें परिवर्तन किए जाते हैं । निगरानी की मौजूदा प्रणाली को उपयुक्त समझा जाता है ।

Irregularities in Nationalised banks in Gujarat

3384. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL. Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether complaints regarding irregularities committed in the Nationalised banks in Gujarat have been received;

(b) if so, the details thereof during the last three years, and

(c) the action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) Complaints by customers against nationalised banks are received by Government and Reserve Bank of India (RBI) from time to time.

(b) According to RBI, their Regional Office at Ahmedabad (under whose jurisdiction the Gujarat State falls) has recieved complaints (including those relating to irregularities) against nationalised banks and private sector banks during the last 3 years as per details below:—

Year	No. of complaints received against the banks
1992 . .	330
1993 . . .	333
1994 . . .	426

(c) Govt./RBI refer these complaints to the banks concerne for appropriate action|redressal|comments. Complaints of serious nature are got investigated by RBI tarough their Regional Offices.

transfer of employees by State Bank of Indore, Janakpuri, New Delhi

3385. SHRI GOVIND RAM MIRI: Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to answer to Unstarred Question 1097 in the Rajya Sabha on 21st March, 1995 and state:

(a) what steps have been taken by the State Bank of Indore to check the union leadors posted at Janakpuri, New Delhi from harassing unnacessarily the employees who are not members of any union;

(b) whether the Bank|Government have received any complaints from the Membere of Parliement as well as the employees against the union leaders; and

(c) whether these complaints have been enquired into, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) to (c) A Member of Parliament and an individual employee of the bank have written to the Govt.|bank alleging harassment of an employee of State Bank of Indore by the union leaders posted at its Janakpuri, Delhi Branch. The bank is investigating the matter and will take appropriate action.

levy of cuctoms tariff on paper

3386. SHRI VISHNU KANT SHASTRI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the reasons to exempt imported newsprint from customs tariff;

(b) what are the reasons for levying customs tariff on paper imported for publicating of books and the rate of such tariff; and

(c) whether Government has received representations from book publishers and students community voicing their concer over levying of customs tariff on paper; if so, what action has been taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) and (b) There are various reasons for levying customs duty of granting exemption from, it which inter-alia, include the nature of the commodtiy, the position of demand and supply, Indigenous and import prices. Paper which is used by book publishers attracts 40 per cent basic customs duty at present.

(c) Yes. Sir. After consideration of these representations, the Government decided to reduce the basic customs duty from 65 per cent to 40 per cent advalorem in the Budget 1995-96.